(b) The procurement price of wheat during the years 1984-85 to 1988-89 had been as under:

Year	Procurement price (Rs. per quintal)
1984-85 . . .	152
1985-86	157
1986-87	162
1987-88	166
1988-89	173

The procurement price of wheat for the year 1989-90 has been fixed as Rs. 183 per quintal.

बीज सम्बन्धी आयात नीति का निर्धारण

2733. **श्री शरद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार बीज संबंधी आयात नीति किस तरह निर्धारित करती है;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या जिन्हें बीज संबंधी आयात-नीति के निर्धारण का काम सौंपा गया है और वे किस-किस क्षेत्र में संबंधित है; और

(ग) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिकों ने चालू बीज तथा नई बीज नीति के संबंध में अपना असंतोष व्यक्त किया है और यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कृषि मंत्रालय विभिन्न अन्य मंत्रालयों के परामर्श से बीजों के आयात संबंधी नीति निर्धारण करता है इसकी घोषणा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है ।

(ख) बीजों के आयात संबंधी नीति निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम बताया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

प्रबंध कार्य में मजदूरों की भागीदारी

2734. **श्री शरद यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के मुद्दे पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के मुद्दे पर पहले भी विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित पहले की योजना का क्या हुआ और उसे अब तक लागू न करने के क्या कारण रहे थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की एक व्यापक योजना को इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के संकल्प सं० एल-56011/1/83-डस्क-I (बी) के तहत अधिसूचित किया गया था । यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) योजना के ब्यौरे दर्शाने वाली प्रतिलिपी अनुबंध में दी गई है [**देखिये** परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं० 146] ।

(ग) और (घ) पहले 30 अक्तूबर, 1975 को तथा पुनः जनवरी 1977 में प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की योजनाओं को अधिसूचित किया गया था । 1975 की योजना विनिर्माण तथा खनन क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए थी जबकि 1977 की योजना वाणिज्यिक तथा सेवा संगठनों में कार्यान्वयन के लिए थी । इन योजनाओं के कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई थी और

दिसम्बर, 1983 में व्यापक योजना को अधिसूचित किया गया था जिसको इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

Identification of Agro Climatic Zones

2735. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have identified the agro-climatic zones in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is a need to adopt strategy for agricultural production agro-climatic zone-wise:

(d) if so, the steps going to be taken by Government in that regard during the Eighth Five Year Plan; and

(e) what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV: (a) and (b) Yes, Sir. For the purposes of Agricultural planning, the country has been delineated into 15 Agro—climatic Zones which are as follows:

1. Western Himalayan Region.
2. Eastern Himalayan Region.
3. Lower Gangetic Plain Region.
4. Middle Gangetic Plain Region.
5. Upper Gangetic Plain Region.
6. Trans—Genetic Plain Region.
7. Eastern-Plateau and Hills Region.
8. Central Plateau and Hills Region.
9. Western Plateau and Hill Region.
10. Southern Plateau and Hills Region.
11. East Coast Plains and Hills Region.
12. West Coast Plain and Ghats Region.
13. Gujarat Plain and Hills Region.
14. Western Dry Region.
15. Island Region.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) The details are as follows:

(i) A Project on Agricultural Planning based on Agroclimatic Regions for the formulation of 8th Plan has been taken up by the Planning Commission.

(ii) Planning teams have been set up for each of the 15 identified agro-climatic regions by the Planning Commission, which is being guided by the High Powered Centre Committee under the Chairmanship of Member Agriculture Planning Commission.

(iii) A Central Project Cell has been set up to provide technical back-up to 15 Regional Planning Teams by the Planning Commission.

(iv) For ensuring proper linkages between the work of various Zonal Planning Teams, a Liaison Group has also been set up in the Planning Commission.

Demand of some Commonly used Steel Items

2736. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is a wide gap between the supply and domestic demand of some commonly used steel items;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to introduce a new scheme to be run on a no-profit no-loss basis to meet the entire demand of commonly used items of steel; and

(d) if so, whether that scheme has been launched?